रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-73 REGISTERED No. D. (D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शनिवार, मई 9, 1981/वैशाख 19, 1903
No. 18] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 9, 1981/VAISAKHA 19, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
Part II—Sec. 3—Sub-Sec. (iii)

(संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं

Orders and Notifications issued by Central Authorities (other than Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1981

आ० अ० 195.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 157-मधुपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दुर्गा मरमू, ग्राम कोल्हू डीह, पो० करो ग्राम, जिला संथाल परगना (बिहार) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत: उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी अपनी उस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दुर्गा मुरमू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/157/80(14)]

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDERS

New Delhi, the 25th February, 1981

O.N. 195.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Durga Murmu, vill. Kalhdih, P.O. Karonpur, distt. Santhal Pargana, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980, from 157-Madhupur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Durga Murmu to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/157/80(14)]

आ०अ० 196.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 157-मधुपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नव कुमार दास, ग्राम बर्मसिया, पो० बस कुप्पी, अंचल-करो, संथाल परगना, बिहार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत: उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी अपनी उस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नव कुमार दास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/157/80(15)]

O.N. 196.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nava Kumar Das, vill. Barmasia, P.O. Baskupi, Anchal Karoa, Santhal Pargana, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980, from 157-Madhupur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nava Kumar Das to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/157/80(15)]

आ०अ० 197.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 157-मधुपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विनोद कुमार मुर्मू, ब्लोक नं० 222, न्यू कालोनी, वार्ड नं० 5, मधुपुर, संथाल परगना, बिहार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिये जाने पर भी अपनी उस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री विनोदकुमार मुर्मू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार-वि०स०/157/80(16)]

O.N. 197.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bindod Kumar Murmu Block No. 222, New Colony, Ward No. 5, Madhupur, Santhal Pargana, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980, from 157-Madhupur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Binod Kumar Murmu to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/157/80(16)]

आ०अ० 198.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए बिहार विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 157-मधुपुर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुरेश चन्द्र दास, कुण्डु बंगला, पो० मधुपुर, जिला संथाल परगना (बिहार) ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और, यत:, उक्त उम्मीदवार ने, उसे सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी अपनी उस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुरेश चन्द्र दास को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० बिहार वि०स०/157/80(17)]
एस० सी० जैन, अवर सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग

O.N. 198.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Suresh Chander Roy, Kundu Bangalow, P.O. Madhupur, Distt. Santhal Pargana, Bihar a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980, from 157-Madhupur constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Suresh Chander Roy to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. BR-LA/157/80(17)]
S. C. JAIN, Under Secy.
Election Commission of India

आदेश

नई दिल्ली, 10 मार्च, 1981

आ०अ० 199.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 145 रामनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम सिंह, ग्रा० तुतुहीपुर, मजरे जैरामपुर, पो० भागीपुर, सीतापुर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/145/80(28)]

ORDERS

New Delhi, the 10th March, 1981

O.N. 199.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Singh, Village Tutuhipur, Majre Jairampur, P.O. Bhagipur, Sitapur, a contesting candidate for general election of the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 145-Ramnagar constituency has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules, made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/145/80(28)]

आ०अ० 200.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 145-रामनगर, निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री श्यामसुन्दर, रामनगर, बाराबंकी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री श्याम सुन्दर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/145/80(29)]

O.N. 200.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shyam Sunder, Ramnagar, Barabanki a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 145-Ramnagar constituency has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shyam Sunder to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/145/80(29)]

नई दिल्ली, 13 मार्च, 1981

आ०अ० 201 :—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1981 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 131 जलालपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम अवध यादव, ग्राम लगरपुर, पो. पवई, तह० फूलपुर, जिला आजमगढ़, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम अवध यादव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र० वि०स०/131/80/(35)]

New Delhi, the 13th March, 1981

O.N. 201.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Awadh Yadav, Village Lagarpur, P.O. Pawai, Tehsil Phulpur, Distt. Azamgarh a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 131-Jalalpur constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declare the said Shri Ram Awadh Yadav to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/131/80(35)]

आ०अ० 202.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 134-अयोध्या निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम कुमार, ग्राम रायपुर, पो० कोटसराय, फैजाबाद, (उ०प्र०) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम कुमार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं उ०प्र०-वि०स०/134/80(36)]

O.N. 202.—Whereas the Election Commission is satisfied Shri Ram Kumar, Village Raipur, P.O. Kotsarai, Faizabad (U.P.), a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 134-Ayodhya constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Kumar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/134/80(36)]

नई दिल्ली, 20 मार्च, 1981

आ० अ० 203—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 63-तिलहर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अमर सिंह, ग्राम गुरगवा, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अमर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/63/80(66)]

New Delhi, the 20th March, 1981

O.N. 203.—Whereas the Election Commission is satisfied Shri Amar Singh, Village Gurgawa, Tehsil Tilhar, Distt. Shahjahanpur, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 63-Tilhar constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Amar Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/63/80(66)]

आ० अ० 204—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 63-तिलहर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम भरोसे, ग्राम गौटिया अत्तू, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम भरोसे को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/63/80(67)]

O.N. 204.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Bharose, Village Gautiya Attu, Tehsil Tilhar, Distt. Shahjahanpur, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 63-Tilhar constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Bharose to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/63/80(67)]

नई दिल्ली, 24 मार्च, 1981

आ० अ० 205.—यत:, निर्वाचन का समाधान हो गया है कि जनवरी 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 40-पडरौना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रमाशंकर राम, ग्राम व पोस्ट भांगा, देवरिया, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रमाशंकर राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-लो०स०/40/80(12)]

New Delhi, the 24th March, 1981

O.N. 205.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramashankar Ram, Village & P.O. Jhanga, Deoria, a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 40-Padrauna constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramashankar Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/40/80(12)]

आ०अ० 206—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 40-पडरौना निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुजाक अली, ग्राम० व पो० कोहरगड्डी, देवरिया, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिये जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुजाक अली को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-लो० स०/40/80(13)]

O.N. 206.—Whereas the Election Commission is satisfied Shri Sujak Ali, Village & P.O. Kohargaddi, Deoria, a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 40-Padrauna constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sujak Ali to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/40/80(13)]

आ०अ० 207.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 168-बस्ती निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भीखीराम, दफाली टोला, पुरानी बस्ती, बस्ती, (उ०प्र०), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भीखी राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/168/80(78)]

O.N. 207.—Whereas the Election Commission is satisfied Shri Bhikhi Ram, Dafali Tola, Purani Basti, Basti (U.P.), a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 168-Basti constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhikhi Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/168/80(78)]

आ०अ० 208.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 52-बरेली सिटी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दिनेश चन्द्र शर्मा, 415, आलमगिरी गंज, बरेली, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दिनेश चन्द्र शर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स० 52/80 (79)]

O.N. 208.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dinesh Chandra Sharma, 415-Alamgiriganj, Bareilly, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 52-Bareilly City constituancy has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dinesh Chandra Sharma to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of

Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/52/80(79)]

आ० अ० 209.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 52-बरेली सिटी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सदा राम लोधी, 370 फाल्गुन गंज, बरेली, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सदा राम लोधी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र० वि०स०-52/80(80)]

O.N. 209.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sada Ram Lodhi, 370, Faltoon Ganj, Bareilly, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 52-Bareilly City constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sada Ram Lodhi to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/52/80(80)]

आ० अ० 210.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 66-शाहजहांपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कमरुद्दीन, मो० ताजूखल, शाहजहांपुर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कमरुद्दीन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स० 66/80(86)]

O.N. 210.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kamruddin, Mo. Tajukhel, Shahjahanpur, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 66-Shahjahanpur constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kamruddin to be disqualified for being chosen as and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/66/80(86)]

आ०अ० 211.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 66-शाहजहांपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मुजफ्फरहुसैन, ग्राम भुडेरी, तहसील सदर, शाहजहांपुर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मुजफ्फर हुसैन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स० 66/80(87)]

O.N. 211.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Muzaffar Hussain, Village Bhuderi, Tehsil, Sadar Shahjahanpur, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 66-Shahjahanpur constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Muzaffar Hussain to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/66/80(87)]

आ०अ० 212.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 66-शाहजहांपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राधेश्याम, मो० बहादुरगंज, शाहजहांपुर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राधेश्याम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र० वि०स० 66/80(88)]

O.N. 212.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Radhey Shyam, Mo. Bahadurganj, Shahjahanpur, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 66-Shahjahanpur constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Radhey Shyam to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/66/80(88)]

नई दिल्ली, 25 मार्च, 1981

आ०अ० 213.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 37-बांसगांव (अ०जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री झिनकू, ग्राम सिकरीडीह बुजुर्ग, पो० सिकरीगंज, जिला गोरखपुर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा श्री झिनकू को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र० लो०स०/37/80(14)]

New Delhi, the 25th March, 1981

O.N. 213.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jhinku, Village Sikridih Bujurg, P.O. Sikriganj, Dist. Gorakpur, a contesting candidate for general election to the Lok Sabha held in January, 1980 from 37-Bansgaon (S.C.) constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jhinku to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date if this order.

[No. UP-HP/37/80(14)]

आ०अ० 214.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 37-बांसगांव (अ०जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मिश्री लाल, ग्राम जगनियां उर्फ शाहपुर जिला गोरखपुर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मिश्री लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-लो०स०/37/80/(15)]

O.N. 214.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mishri Lal, Village Jignia Urf Shahpur, Dist. Gorakhpur, a contesting candidate for general election to the Lok Sabha held in January, 1980 from 37-Bansgaon (S.C.) constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mishri Lal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/37/80(15)]

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1981

आ०अ० 215.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 301-औरैया निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री संतोष कुमार, जमुना रोड, औरैया, जिला इटावा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त संतोष कुमार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/301/80/(89)]

New Delhi, the 27th March, 1981

O.N. 215.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shi Santosh Kumar, Jamuna Road, Auraiya Distt. Etawah, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 301-Auraiya constituency has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Santosh Kumar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/301/80(89)]

आ०अ० 216.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 301 औरैया निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हरीश कुमार मुहल्ला पढ़ीन दरवाजा, कस्बा औरैया, जिला इटावा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हरीश कुमार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र० वि०स०/301/80(90)]

O.N. 216.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Harish Kumar, Mohlla-Padhin Darwaja, Kasba Auraiya, Distt. Etawah, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 301-Auraiya constituency has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder ;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Harish Kumar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/301/80(90)]

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1981

आ०अ० 217.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 31-बहराइच निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सालिक राम मो० भेचूबाबा, इकौना, बहराइच, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सालिक राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र० लो०स०/31/80(16)]

New Delhi, the 30th March, 1981

O.N. 217.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Salik Ram, Mo. Bhichubaba, Ekauna, Baharaich, a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 31-Bahraich constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Salik Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/31/80(16)]

आ०अ० 218.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 48-आंवला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हेमपाल सिंह, राजपुर कलां, बरेली, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हेमपाल सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र० वि०स०/48/80(96)]

O.N. 218.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hempal Singh, Rajpur Kalan, Bareilly, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 48-Amla constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hempal Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/48/80(96)]

आ०अ० 219.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 57-पीलीभीत निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अब्दुल माबूद, मो० मोहम्मद वासिल, पीलीभीत, लोक प्रतिनिधित्व

अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अब्दुल माबूद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/57/80(97)]

O.N. 219.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Abdul Mabood, Mo. Mohammad Wasil, Pilibhit, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 57-Pilibhit constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Abdul Mabood to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/57/80(97)]

आ०अ० 220.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 79-सीतापुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री जयनारायण शुक्ला, ग्राम बहारापुर, पो० महोली, जिला सीतापुर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री जयनारायण शुक्ला को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र० वि०स०/79/80(98)]

O.N. .—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jainarayan Shukla, Village Bahrapur, P.O. Maholi, Distt. Sitapur, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 79-Sitapur constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jainarayan Shukla to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/79/80(98)]

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1981

आ०अ० 221.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 58-बरखेड़ा (अ०जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राजाराम, मो० मोहतशिम खां, पीलीभीत, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और अतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राजाराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र० वि०स०/58/80(99)]

New Delhi, the 31st March, 1981

O.N. 221.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Raja Ram, MO. Mohatshim Khan, Pilibhit, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh legislative Assembly held in May, 1980 from 58-Barkhera (S.C.) constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Raja Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/58/80(99)]

आ०अ० 222.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 59-बिसालपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पुत्तन, मो० हबीबुल्ला खां (व०) बीसलपुर, जिला पीलीभीत, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री पुत्तन को संसद के किसी भी सदन के या

किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/59/80(100)]

O.N. 222.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Putan, Mo. Habibllah Khan (S) Bisalpur, Distt. Pilibhit, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 59-Bisalpur constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Puttan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/59/80/(100)]

आ०अ० 223.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 60-पूरनपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री हंसराम, ग्राम सुल्तानपुर, तह० पुवायां, जिला शाहजहांपुर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री हंसराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/60/80(101)]

O.N. 223.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Hans Ram, Village Sultanpur, Tehsil Puwayan, Distt. Shahjahanpur, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 60-Puranpur constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Hans Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/60/80(101)]

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 1981

आ०अ० 224.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 371-गंगीरी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भूदेव सिंह वर्मा, ग्राम लधुपुरा, पो० छर्रा, जिला अलीगढ़ (उ०प्र०) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भूदेव सिंह वर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/371/80(104)]

New Delhi, the 1st April, 1981

O.N. 224.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhoodev Singh Verma, Village-Ludhpura, P. O. Chharra, District-Aligarh ; Uttar Pradesh, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 371-Gangiri constituency has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder ;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Bhoodev Singh Verma to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/371/80(104)]

आ०अ० 225.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 76-महमूदाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विद्याधर, बकछुआ बाजार, सीतापुर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री विद्याधर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/76/80(105)]

O.N. 225.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Vidyadhar, Wakhuwa Bazar, Sitapur a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 76-Mahmudabad constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas, the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vidyadhar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/76/80(105)]

नई दिल्ली, 2 अप्रैल, 1981

आ० अ० 226.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी 1980 में हुए लोकसभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 53-राबर्टसगंज (अ०जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रघुनाथप्रसाद 109/364, रामकृष्ण नगर, कानपुर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रघुनाथ प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र० लो०स०/53/80(19)]

New Delhi, the 2nd April, 1981

O.N. 226.—*Whereas the Election Commission is satisfied* that Shri Raghunath Prasad, 109/364, Ramkrishan Nagar, Kanpur, a contesting candidate for general election to the Lok Sabha held in January, 1980 from 53-Robertsganj (S.C.) constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Raghunath Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/53/80(19)]

आ० अ० 227.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 74-बेहटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दुजई राम (अ०जा०), उमरिया, मजरा पिपरिया भदफर, जिला सीतापुर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दुजई राम (अ०जा०) को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/74/80(108)]

O.N. 227.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dujai Ram (SC), Umaria, Majro Pipariya, Bhadfar, Distt. Sitapur a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 74-Behta constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dujai Ram (SC) to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/74/80(108)]

आ० अ० 228.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 74-बेहटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री माता प्रसाद, बेलामऊ कलां, मुमताजपुर, जिला सीतापुर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री माता प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/74/80(109)]

O.N. 228.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mata Prasad, Welamaukalan, Mumtajpur, Sitapur a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from *74-Behta constituency has failed to lodge an account of* his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mata Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/74/80(109)]

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 1981

आ०अ० 229.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 61-पुवाया (अ०जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ऋषिदेव, निवासी, जेरा रहीमपुर, तहसील जलालाबाद, जिला शाहजहांपुर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है,

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए, जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री ऋषिदेव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख के तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित-घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि०स०/61/80(111)]

New Delhi, the 4th April, 1981

O.N. 229.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rishidev, R/o Jera Rahimpur, Tehsil Jalalabad, Distt. Shahjahanpur, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 61-Puwayan (SC) constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rishidev to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/61/80(111)]

आ०अ० 230—यत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 61-पुवायां (अ०जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बाबूराम, मो० कसभरा, पुवायां, जिला शाहजहांपुर, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत उक्त उम्मीदवार ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत. अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बाबू राम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स० 61/80(112)]

O.N. 230.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Babu Ram, Mo. Kasbhara, Puwayan, Distt. Shahjahanpur, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 61-Puwayan (SC) constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Babu Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/61/80(112)]

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1981

आ०अ० 231—यत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 328-झांसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मुन्नालाल, 20-गोखलेनगर, कोंच, झांसी (उ०प्र०) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित नहीं है,

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मुन्ना लाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/328/80(113)]

New Delhi, the 6th April, 1981

O.N. 231.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Munna Lal, 20-Gokhale Nagar, Konch, Distt. Jhansi (U.P.), a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 328-Jhansi constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Munna Lal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/328/80(113)]

आ०अ० 232—यत निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 328-झांसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रमेश प्रसाद 137-हजरयाना, झांसी, (उ०प्र०) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यत उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रमेश आजाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि०स० 328/80(114)]

O.N. 232.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramesh Azad, 137, Hajaiyana, Jhansi (U.P.), a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 328-Jhansi constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramesh Azad to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/328/80(114)]

नई दिल्ली, 7 अप्रैल, 1981

आ० अ० 233.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 7-करोल बाग (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कालूराम, मं० नं० 5261, गली नं० 7, कृष्णा नगर, दिल्ली लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कालू राम को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० दिल्ली-लो० स०/7/80(1)]

New Delhi, the 7th April, 1981

O.N. 233.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kalu Ram, H.No. 5261, Gali No. 7, Krishan Nagar Delhi, a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 7-Karol Bagh (S.C.) constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kalu Ram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. DL-HP/7/80(1)]

आ० अ० 234—यतः, निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 7—करोल बाग (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री बाबूलाल टोरी, 4945/40, रैगरपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बाबू लाल टोरी को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० दिल्ली-लो० स० 7/80(2)]

O.N. 234.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Babu Lal Tori, 4945/40, Regharpura, Karol Bagh, New Delhi, a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 7-Karol Bagh (S.C.) constituency has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder;

And whereas, after considering the representation made by the said candidate, the Election Commission is further satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Babu Lal Tori to be disqualified for being chosen as, and for being, a member or either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. DL-HP/7/80(2)]

आ० अ० 235.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 86-हरदोई निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम प्रताप सिंह, ग्राम उदरा, नेवालिया, डा० उदरा, जिला हरदोई, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम प्रताप सिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र० वि० स० 86/80(115)]

O.N. 235.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Pratap Singh, Village Udra Newalia, P. O. Udra, Distt. Hardoi, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 86-Hardoi constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Pratap Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/86/80(115)]

आ० अ० 236.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 88-पिहानी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दिनेश चन्द्र, मो० दिलेरगंज, कस्बा शाहाबाद, हरदोई, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दिनेश चन्द्र को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स० 88/80(116)]

O.N. 236.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dinesh Chandra, Mo. Dilerganj, Kasba Shahabad, Hardoi, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 88-Pihani constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dinesh Chandra to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/88/80(116)]

आ० अ० 237.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 88-पिहानी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम सिंह, सरेलू, पो० राबा, जिला हरदोई, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रामसिंह को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए, आदेश इस की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र० वि० स० 88/80(117)]

O.N. 237.—Whereas the Election Commission is satisfied that Ramsingh, Village Sarehaloo, P.O. Rabha, Distt. Hardoi, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 88-Pihani constituency has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramsingh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/88/80(117)]

आ० अ० 238.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 90-बिलग्राम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम सरन, ग्राम छोछपुर, डा० मन्सूरापुर, तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम सरन को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है;

[सं० उ० प्र०-वि० स०/90/80(118)]

O.N. 238.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ramsaran, Village Chhochhpur, P.O. Mansurapur, Tehsil Bilgram, Distt. Hardoi, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 90-Bilgram constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ramsaran to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/90/80(118)]

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1981

आ० अ० 239.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 85-अहिरोरी (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम भरोसे, ग्रा० डा० बालामऊ, जिला हरदोई, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित

अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम भरोसे को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र० वि० स०/85/80(119)]

New Delhi, the 8th April, 1981

O.N. 239.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Bharose, Village-P.O. Balamau, District Hardoi, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 85-Ahirori (S.C.) constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Bharose to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/85/80(119)]

आ० अ० 240:—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 89-शाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ज्वाला शंकर, मो० दिलेरगंज, कस्बा शाहाबाद, जिला हरदोई, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री ज्वाला शंकर को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/89/80(120)]

O.N. 240.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Jwala Shankar, Mo. Dilerganj, Kasba Shahabad Distt. Hardoi a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 89-Shahbad constituency has failed to lodge an account of his election expenses in the manner required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Jawala Shankar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/89/80(120)]

आ० अ० 241.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 75-बिसवां निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दुर्जन, जगनेह्या, राजा करनाई, सीतापुर (यू०पी०) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत: उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दुर्जन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[स०उ०प्र०-वि०स०/75/80(121)]

O.N. 241.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Durjan, Jagnehaya, Raja Karnai, Sitapur (U.P.) a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 75-Biswan constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Durjan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/75/80(121)]

आ०अ० 242.—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 96-भगवन्त नगर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री फतेह बहादुर सिंह ग्राम व पो० अकबाबाद, जिला उन्नाव, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री फतेह बहादुर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/96/80(122)]

O.N. 242.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Fateh Bahadur Singh, Village and P.O. Akwabad, District Unnao, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 96-Bhagwant Nagar constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Fateh Bahadur Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/96/80(122)]

नई दिल्ली, 19 अप्रैल 1981

आ०अ० 243—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 141-हैदर गढ़ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दुखहरन, ग्राम बहरामपुर, पो० हैदरगढ़, जिला बाराबंकी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दुखहरन को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/141/80(123)]

New Delhi, the 9th April, 1981

O.N. 243.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dukhharan, Village Behrampur, P.O. Haidergarh, Distt. Barabanki, a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 141-Haidergarh constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dukhharan to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/141/80(123)]

नई दिल्ली, 14 अप्रैल, 1981

आ० अ० 244:—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 97-पुरवा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री धर्म प्रकाश, चन्दनगंज, मौरावां, उन्नाव, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री धर्म प्रकाश को संसद् के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/97/80(124)]

New Delhi, the 14th April, 1981

O.N. 244.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dharm Parkash, Chandanganj Maurawan, Unnao a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 97-Purwa constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dharm Prakash to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/97/80(124)]

आ० अ० 245.—यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 97-पुरवा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री रसिक बिहारी श्रीवास्तव, मो० कस्तोलवा, पुरवा, उन्नाव, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री रसिक बिहारी श्रीवास्तव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स० 97/80 (125)]

O.N 245.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rasik Bihari Shrivastava, Mo. Kastolwa, Purwa, Unnao a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 97-Purwa constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri

Rasik Bihari Shrivastava to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of his order.

[No. UP-LA/97/80(125)]

आ० अ० 246.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 71-एटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री भगवान, नगला टोरी मजरा चिलौली अहमदपुर, डा० चिलौली अहमदपुर, जिला एटा (यू०पी०) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री भगवान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-लो०स० 71/80 (20)]

O.N. 246.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Bhagwan Nagla Tori Majra Chiloli Ahmedpur, Post Chiloli Ahmedpur, Distt. Etah (U.P.) a contesting candidate for general election to the Lok Sabha from Uttar Pradesh held in January, 1980 from 71-Etah constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Bhagwan to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP HP/71/80(20)]

आ० अ० 247.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 71-एटा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री यज्ञ दत्त, 53, अरुणा नगर, एटा (यू०पी०) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री यज्ञ दत्त को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-लो०स०/71/80(21)]

O.N. 247.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Yagya Dutt 53, Aruna Nagar Etah (U.P.) a contesting candidate for general election to the Lok Sabha from Uttar Pradesh held in January, 1980 from 71-Etah constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Yagya Dutt to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/71/80(21)]

आ० अ० 248.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 68-फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मान सिंह, ग्राम होतेपुर, पो०आ० बिलसारी जिला फर्रुखाबाद (उ०प्र०), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मान सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-लो०स०/68/80 (22)]

O.N. 248.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Man Singh, Village Hotepur, P.O. Bilasari, Distt. Farrukhabad (U.P.) a contesting candidate for general election to the Lok Sabha from Uttar Predesh held in January, 1980 from 68-Farrukhabad constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act the Election Commission hereby declares the said Shri Man Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No UP-HP/68/80(22)]

आ० अ० 249.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 68-फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री विद्या सागर, ग्रा० तथा पो०आ० गिरौली, फर्रुखाबाद (उ०प्र०), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं,

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और

निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री विद्या सागर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-लो०स० 68/80 (23)]

O.N. 249.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Vidya Sagar, V. & P.O. Sirauli, Farrukhabad (U.P.) a contesting candidate for general election to the Lok Sabha from Uttar Pradesh held in January, 1980 from 68-Farrukhabad constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Vidya Sagar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the adte of this order.

[No. UP-HP/68/80(23)]

आ० अ० 250.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 68-फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम बाबू बाजपई, 2/245 खाराना, भगवत गली, फर्रुखाबाद (उ०प्र०), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम बाबू बाजपई को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-लो०स०/68/80 (24)]

O.N. 250.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Babu Bajpai, 2/245, Kha'rana, Bhagwat St., Farrukhabad (U.P.) a contesting candidate for general election to the Lok Sabha from Uttar Pradesh held in January, 1980 from 68-Farrukhabad constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Babu Bajpai to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/68/80(24)]

आ० अ० 251.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 68-फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार बाबा कृष्ण चन्द्र मनोब सेवा आश्रम, ग्रजगंज, पो०आ० फतेहगढ़, जिला फर्रुखाबाद, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री बाबा कृष्ण चन्द्र को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-लो०स० 68/80 (25)]

O.N. 251.—Whereas the Eelection Commission is satisfied that Shri Baba Krishna Chandra, Manob Sewa Ashram, Grajganj, P.O. Fatehgarh, Distt. Farrukhabad a contesting candidate for genedal election to the Lok Sabha from Uttar Pradesh held in January, 1980 from 68-Farrukhabad constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure,

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Baba Krishna Chandra to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/68/80(25)]

आ० अ० 252.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 68-फर्रुखाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम आश्रय दीक्षित, ग्रा० व पो० आ० मनझाना, जिला फर्रुखाबाद, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम आश्रय दीक्षित को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र० लो०स० 68/80 (26)]

O.N. 252.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Ashray Dikshit, V. & P.O. Manjhana, Distt. Farrukhabad a contesting candidate for general election to the Lok Sabha from Uttar Pradesh held in January, 1980 from 68-Farrukhabad constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Ashray Dikshit to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/68/80(26)]

आ० अ० 253.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 70-जलेसर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दलबीर सिंह, ग्राम तिलामई, डा० रेजुआ, तहसील जलेसर, जिला एटा (उ०प्र०), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दलबीर सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-लो०स०/70/80 (27)]

O.N. 253.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Dalwir Singh, Village Tilamai, Post Renjua, Teh. Jalesar, Distt. Etah (U.P.) a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in January, 1980 from 70-Jalesar constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Dalwir Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/70/80(27)]

आ० अ० 254.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 70-जलेसर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री दीवान सिंह, ग्राम बदनपुर काजीपुर, डा० सकरौली, तहसील जलेसर, जिला एटा (उ०प्र०), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री दीवान सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-लो०स०/70/80 (28)]

O.N. 254.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Diwan Singh, Village Badanpur Kajipur, Post Sakrauli, Tehsil Jalesar, District Etah (U.P.), a contesting candidate for general election to the Lok Sabha from Uttar Pradesh held in January 1980 from 70-Jalesar constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Diwan Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/70/80(28)]

आ० अ० 255.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 70-जलेसर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नेपाल सिंह, यादव नगर, एटा (उ०प्र०), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नेपाल सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-लो०स०/70/80 (29)]

O.N. 255.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nepal Singh, Yadav Nagar, Etah (U.P.) a contesting candidate for general election to the Lok Sabha from Uttar Pradesh held in January, 1980 from 70-Jalesar constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nepal Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/70/80(29)]

आ० अ० 256.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 70-जलेसर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री योगेन्द्र सिंह यादव, महात्मा गांधी मार्ग, एटा (उ०प्र०) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री योगेन्द्र सिंह यादव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-लो०स०/70/80 (30)]

O.N. 256.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Yogender Singh Yadav, Mahatma Gandhi Marg, Etah (U.P.) a contesting candidate for general election to the Lok Sabha from Uttar Pradesh held in January, 1980 from 70-Jalesar constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rule made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Yogender Singh Yadav to be disqualified for chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/70/80(30)]

आ० अ० 257.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 70-जलेसर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम प्रसाद, मकान नं० 28, ग्राम टुण्डला खाम, पो० टुण्डला आगरा (उ०प्र०), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राम प्रसाद को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-लो०स०/70/80 (31)]

O.N. 257.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Prasad, House No. 28, Vill. Tundla Kham, Post Tundla, Distt. Agra (U.P.) a contesting candidate for general election to the Lok Sabha from Uttar Pradesh held in January, 1980 from 70-Jalesar constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Prasad to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/70/80(31)]

आ० अ० 258.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश से लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 70-जलेसर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री सुखवासी, मकान नं० 216 ग्राम सोना, पोस्ट टुण्डला, जिला आगरा (उ०प्र०), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री सुखवासी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-लो०स०/70/80 (32)]

O.N. 258.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Sukhwasi, House No. 216, Vill. Sona, Post Tundla, Distt. Agra (U.P.) a contesting candidate for general election to the Lok Sabha from Uttar Pradesh held in January, 1980 from 70-Jalesar constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Sukhwasi to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-HP/70/80(32)]

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1981

आ० अ० 259--यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 157-उतरौला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोहम्मद इद्रीश ग्राम रमवापुर कला, पो० उतरौला, जिला गोंडा, (उ०प्र०), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री महोम्मद इद्रीस को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/157/80 (126)]

New Delhi, the 15th April, 1981

O.N. 259.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mohammad Idris, Village Ramwapur Kalan, P.O. Utraula, Distt. Gonda (U.P.) a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 157-Utraula constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Mohammad Idris to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[UP-LA/157/80(126)]

आ० अ० 260.--यत, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 157-उतरौला निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री राम मनोरथ, ग्राम जोगीबिर, पोस्ट उतरौला, जिला गोण्डा, (उ०प्र०), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत, अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री राममनोरथ को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ०प्र०-वि०स०/157/80(127)]

O.N. 260.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ram Manorath, Village Jogibir, P.O. Utraula, Distt. Gonda (U.P.), a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 157-Utraula constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ram Monorath to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/157/80(127)]

आ० अ० 261.--यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 1-अम्बाला (अ० जा०) निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवार श्रीमती विमला देवी, गांव गोविन्दपुरा, डा० जगाधरी, जिला अम्बाला (हरियाणा), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रही है;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्रीमती विमला देवी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० हरि०-लो० स०/1/80(1)]

O.N. 261.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shrimati Bimla Devi, Village Gobindpura, P.O. Jagadhari, Distt. Ambala (Haryana) a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 1-Ambala (SC) constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shrimati Bimla Devi to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HN-HP/1/80(1)]

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1981

आ० अ० 262--यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि जनवरी 1980 में हुए लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 3-करनाल निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अमीलाल, गांव व डा० संगोहा, जिला करनाल (हरियाणा), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अमीलाल को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० हरि०-लो० स०/3/80(3)]

New Delhi, the 16th April, 1981

O.N. 262.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ami Lal, Village and P.O. Sangoha, Distt. Karnal (Haryana) a contesting candidate for general election to the House of the People held in January, 1980 from 3-Karnal constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ami Lal to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HN-HP/3/80(3)]

आ०अ० 263.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 92-बांगरमऊ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री कन्हैया लाल वर्मा, ग्राम भटौली, पो० अटवाबैक, जिला उन्नाव (उ० प्र०), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री कन्हैया लाल वर्मा को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र०-वि० स०/92/80 (139)]

O.N. 263.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Kanhaiya Lal Verma, Village Bhatauli, P.O. Atwaback, Distt. Unnao (U.P.) a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 92-Bangarmau constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Kanhaiya Lal Verma to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/92/80(139)]

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 1981

आ०अ० 264.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए उत्तर प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 232-जमानिया निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लालमनी, जिगना सिसोदा, वाराणसी (उ० प्र०), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों में कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री लालमनी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० उ० प्र० वि० स०/232/80(41)]
ओ० ना० नागर, अवर सचिव
भारत निर्वाचन आयोग

New Delhi, the 24th April, 1981

O.N. 264.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Lalmani, Jigana Sisoda, Varanasi (U.P.) a contesting candidate for general election to the Uttar Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 232-Zamania constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Lalmani to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. UP-LA/232/80(41)]
O. N. NAGAR, Under Secy.
Election Commission of India

आदेश

नई दिल्ली, 30 मार्च, 1981

आ० अ० 265.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए 63-पालघर (अ०ज०जा०) निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शिगड़े अर्जुन ककाडया मु० नंदगाव उर्फ मनोर डा० मनोर, तालुका पालघर, जिला थाने, महाराष्ट्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत: उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शिंगड़े अर्जुन ककाड़या को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/62/80 (29)]

ORDERS

New Delhi, the 30th March, 1981

O.N. 265.—Whereas, the Election Commission is satisfied that Shri Shingade Arjun Kakadya, At-Nandgaon Turf Manor, Post Manor, Taluk Palghar, District Thane (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 62-Palgarh (ST) constituency has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shingade Arjun Kakadya to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/62/80(29)]

आ०अ० 266.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 110-बोरगांव मंजू निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोर मनोहर, रतीराम, विटल फैल, नजदीक उमारी नाका जिला अकोला (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मोर मनोहर रतीराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/110/80 (30)]

O.N. 266.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri More Manohar Ratiram, Vital Fail, Near Umari Naka, District Akola, Akola (Maharashtra) a constesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assebmly held in May, 1980 from 110-Borgaon Manju constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri More Manohar Ratiram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. HT-LA/110/80(30)]

आ०अ० 267.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 110-बोरगांव मंजू निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री शेगोकार, रामचन्द्रा अर्जुन, मा० ए० उमारी तालुका व जिला अकोला (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री शेगोकार रामचन्द्रा अर्जुन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि०स०/110/80 (31)]

O.N. 267.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shegokar Ramchandra Arjun, At, Post Umari, Tq. and District Akola (Maharashtra) a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 110-Borgaon Manju constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shegokar Ramchandra Arjun to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order

[No. MT-LA/110/80(31)]

आ० अ० 268.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 110-बोरगांव मंजू निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री श्रावन शेकोजी इंगले, मु० डा० शिरोनी, (शीवर) तालुका व जिला अकोला (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत: उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री श्रावन शेकोजी इंगले को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा वि०स०/110/80 (32)]

O.N. 268.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Shrawan Shekoji Ingle, At Post Shioni (Shiwar) Tq and District Akola (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 110-Borgaon Manju constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Shrawan Shekoji Ingle to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/110/80(32)]

आदेश

नई दिल्ली 3, अप्रैल, 1981

आ० अ० 269—यत: निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 224-इटारसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री अनिल कुमार अवस्थी, मालवीय गंज, इटारसी (मध्य प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री अनिल कुमार अवस्थी को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म० प्र०-वि०स०/224/80(22)]

ORDER

New Delhi, the 3rd April, 1981

O.N. 269.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Anil Kumar Awasthi, Malviya Ganj, Atarsi, (Madhya Pradesh), a contesting candidate for general election to the Marhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 224-Atarsi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Anil Kumar Awasthi to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/224/80(22)]

आ० अ० 270—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 143-भंडारा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री नंदुरकार शामराव आत्माराम, शास्त्री नगर, भंडारा, जिला भंडारा (महाराष्ट्र), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 10-क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री नंदुरकार शामराव आत्माराम को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० महा-वि० स०/143/80 (34)]

O.N. 270.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Nandurkar Shamrao Atmaram, Shastrinagar, Bhandara, Bhandara District (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 143-Bhandara constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Nandurkar Shamrao Atmaram to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/143/80(34)]

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 1981

आ० अ० 271.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 271-इन्दौर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ऋषि कुमार शुक्ल, 7/2-ए, मोतीतबेला, इन्दौर, (मध्य प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री ऋषि कुमार शुक्ल, को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० म०प्र० वि०स०/271/80(23)]

New Delhi, the 6th April, 1981

O.N. 271.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Rishi Kumar Shukla, 7/2A, Motitabela, Indore (Madhya Pradesh), a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh, Legislative Assembly held in May, 1980 from 271-Indore-2 constituency, has failed to lodge an account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Rishi Kumar Shukla to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/271/80(23)]

आ० अ० 272.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 271-इन्दौर निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री महेश ओंकार, 16/2 नन्दा नगर, इन्दौर-3(मध्य प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री महेश ओंकार को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० म०प्र० वि०स०/271/80(24)]

O.N. 272.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Mahessh Onkar, 16/2, Nandanagar, Indore-3 (Madhya Pradesh), a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held in May, 1980 from 271-Indore constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representaion of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Flection Commission hereby declares the said Shri Mahesh Onkar to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/271/80(24)]

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 1981

आ० अ० 273.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए मध्य प्रदेश विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 279-बागली निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मड़िया पहाड़ सिंह, ग्राम पानकुआं, पोस्ट पुन्जापुरा, तहसील बागली, जिला देवास (मध्य प्रदेश), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतदद्वारा उक्त श्री मड़िया पहाड़ सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० म०प्र० वि०स०/279/80(27)]

New Delhi, the 8th April, 1981

O.N. 273.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Madia Paha. Singh, Village Pankunva, Post Punjapura, Tehsil Bagli, District Dewas (Madhya Pradesh), a contesting candidate for general election to the Madhya Pradesh Legislative Assembly held on May, 1980 from 279-Bagli constituency, has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he had no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Flection Commission hereby declares the said Shri Madia Pahar Singh to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MP-LA/279/80(27)]

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1981

आ० अ० 274.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 244-मुलशी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री पासलकर रामचन्द्र बाबूराव, 658 गोखले नगर, पुने-16, (महाराष्ट्र), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतदद्वारा उक्त श्री पासलकर रामचन्द्र बाबूराव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं० महा-वि०स०/244/80(40)]

New Delhi, the 15th April, 1981

O.N. 274.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Pasalkar Ramchandra Baburao, 658-Gokhalenagar, Pune-16 (Maharashtra), a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 244-Mulshi constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder ;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Pasalkar Ramchandra Baburao to be disqualified for being chosen as, and for being, a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/244/80(40)]

आ०अ० 275.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 257-भोर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री घडागे नामदेव पन्डुरंग, आनन्द नगर, नागपुर चाल, पुने 411006 महाराष्ट्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री घडागे नामदेव पन्डुरंग को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० मह-वि०स०/257/80(41)]

O.N. 275.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Ghadage Namdeo Pandurang, Anandnagar, Nagpur Chawl, Pune-411006, a contesting candidate for general election to the Legislative Assembly held in May, 1980 from 257-Bhor Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Ghadage Namdeo Pandurang to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/257/80(41)]

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1981

आ०अ० 276.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 251-कन्टोनमेन्ट निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री तूपे अनन्त राव बाजीराव, मकान नं० 83, मालवाडी, हडपसर, पूने-28 (महाराष्ट्र), लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री तूपे अनन्त राव बाजीराव को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० मह वि०स०/251/80(46)]

New Delhi, the 16th April, 1981

O.N. 276.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Tupe Anantrao Bajirao, House No. 83, Malwadi, Hadapsar, Pune-28, a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 251-Pune Cantonment Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after the notice, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Tupe Tnantrao Bajirao to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this o der.

[No. MT-LA/251/80(46)]

आ०अ० 277.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई, 1980 में हुए महाराष्ट्र विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 252-शिरूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री मोरे श्याम कान्त दामोदर, मु० दिहुगांव, तालुका हवेली (महाराष्ट्र) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यतः उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, और निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री मोरे श्याम कान्त दामोदर को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० मह वि०स०/252/80(47)]

O.N. 277.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri More Shymkant Damodar, At & Post Dehugaon, Taluka-Haveli, Maharashtra, a contesting candidate for general election to the Maharashtra Legislative Assembly held in May, 1980 from 252-Shirur Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses at all as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notice, not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he h s no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri More Shymkant Damodar to be disqualified for being chosen as, and for being a membe. of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. MT-LA/252/80(47)]

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1981

आ०अ० 278.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 111 के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग, सन् 1980 की निर्वाचन अर्जी संख्या 5 में दिए गए बम्बई उच्च न्यायालय के तारीख 9 फरवरी, तथा 10 अप्रैल, 1981 के आदेश तथा रिपोर्ट को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

[सं० 82/महा०/ (5/80)/81]

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 1981

O.N. 278—In pursuance of section 111 of the Representation of the People Act, 1951 the Election Commission hereby publishes the Order and Report dated 9th February and 10th April, 1981, respectively, of the High Court of Judicature at Bombay in Election Petition No 5 of 1980.

IN THE HIGH COURT OF JURISDICATURE AT BOMBAY

ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION

Election Petition No 5 of 1980

Plaintiff
Petitioner

Versus

Defendant
Respondent

Coram Bharucha J
Dated 9-2 1981

Called for Withdrawal

Mr Sudhir G Naik with Mr Gamadia—for Petitioner

Mr Jagdish Mehta of M/s Bhaishanker Kanga & Girdharilal other Respondents absent for Respondent

Mr Naik undertakes to file his appearance on behalf of the Petitioner within a week from today

Notice of withdrawl of Petition published in the official Gazette taken on file

P C Petition allowed to be withdrawn with no order as for costs

Petition to be advertised in the Central Government Gazette as required under section 110(b) of the Representation of People Act

Costs of Publication to come out of the security deposit deposited in the office Balance to be refunded to the Petitioner

(Extract of letter No B/dated 10th April, 1981 from High Court, Bombay)

Re —Election Petition No 5 of 1980
Smt Shalinibai V Patil Petitioner

Vs

Shri Y B Chavan & Ors Respondents

Report of withdrawal by the High Court under section 111 of People Act, 1951

x x x x x

2 Pursuant to the Order dated 9th February 1981 the necessary notice under section 110(3) of the Representation of the People Act, 1951 for withdrawal of the above Election Petition was published in the Gazette of India dated 21st March, 1981 (Part 4, Page 51)

As no person has applied for substitution in place of the Petitioner within 14 days from the date of said publication i e upto 6th April, 1981 the above Petition stands withdrawn as required under section 111 of the said Act

This letter is by way of report of the withdrawal of the Election Petition as required under Section 111 of the Representation of the People Act

[No 82/MT/(5/80)/81]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 1981

आ० अ० 279 —लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 106 के अनुसरण मे निर्वाचन आयोग, सन् 1980 की निर्वाचन अर्जी संख्या 2 मे दिए गए अहमदाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 28 1-1981 के निर्णय को एतद्द्वारा प्रकाशित करता है।

[सं० 82-गुज/(2/1980)/81]

आदेश से,

धर्मवीर अवर सचिव।

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd April, 1981

O.N 279—In pursuance of section 106 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby publishes the order pronounced on 28th January, 1981 by the High Court of Judicature at Ahmedabad in Election Petition No 2 of 1980.

IN THE HIGH COURT OF GUJARAT AT AHMEDABAD

(District Baroda)

Election Petition No. 2 of 1980

In the matter of Section 33 and other relevant provisions of the Representation of the People Act, 1951,

AND

In the matter of Rules 2(g), 4 10, 11 and other relevant provisions of the Conduct of Election Rules, 1961

AND

In the matter of a petition under Section 80 of the Representation of the People Act, 1951

AND

In the matter between,

Rathwa Mohansinh Chhotubhai, residing at village Pavi Jetpur District, Baroda

Petitioner

Versus

1 Amarsingbhai Virayabhai Rathwa residing at village Vijli, Post Mankedi, Taluka Chhota Udepur, District, Baroda

2 Tadvi Kanubhai Somabhai (Panwala), residing at Natwarpura, Palace Road, Chhota Udepur, District Baroda

Respondents

28-1-1981

Mr N H BHATT

Mr J G Shah with Miss D T Shah—for the petitioner

Mr J M Thakore, Advocate General, with Mr H M Mehta—for the respondent No 1

The respondent No 2 served

Attorney General served

Coram N H Bhatt, J
(28-1 1981)

Oral Judgment:

This is an Election petition filed by one Rathwa Mohansinh Chhotubhai, hereinafter referred to as 'the petitioner', challenging the election of the respondent No 1 to the Parliament in the beginning of the year 1980 from Chhota-Udepur Constituency, which was reserved for a Scheduled Tribe candidate The only ground on which the petitioner, who lost the election, challenges the election of the respondent No is that the respondent No 1 had not set out in his nomination forms, four in number and produced at Annexure A 1 to A-4 to this petition, the specific Tribe to

which he belongs and thus had non-complied with the mandatory requirement of section 33(2) of the Representation of the People Act, 1951, hereinafter referred to as 'the R. P. Act, 1951' for brevity's sake which enjoins as follows :—

"In a constituency where any seat is reserved, a candidate shall not be deemed to be qualified to be chosen to fill that seat unless his nomination paper contains a declaration by him specifying the particular caste or tribe of which he is a member and the area in relation to which that caste or tribe is a Scheduled Caste or, as the case may be, a Scheduled Tribe of the State."

2. In the petition, as was originally filed, there were two prayers, viz. (1) to get the election of the respondent No. 1 declared void ; and (2) to declare the petitioner elected as a member of the House of the People from the aforesaid Chhotaudepur Constituency reserved for the Scheduled Tribe. However, by purshis, ex. 21 dated 21st December, 1980 the second prayer was not pressed. In the petition, was orginally filed, the other candidate in the field, the respondent No. 2, was also impleaded as a party and it was necessary to do so at that stage because the petitioner wanted to get himself declared duly elected. It was alleged in the petition that the nomination forms of the respondent No. 2 also were suffering from the same infirmity, but in view of the statement at Ex. 21 referred to above, I am not required to deal with that question pertaining to the validity or otherwise of the nomination papers of the respondent No. 2. The only question of substance, therefore, that survives in this petition is whether in terms of section 100(2)(d) of the R. P. Act of 1951, the result of the election in so far as it concerns a returned candidate has been materially affected by the improper acceptance of the respondent No. 1's nomination. In a case where it is alleged that the nomination of a candidate declared successful at the election is on the plea of improper acceptance of any nomination of such a candidate, the question whether the result has been materially affected or not would not arise, because it is evident that if the nomination of the respondent No. 1 had not been accepted, the result of the election, as it is now holding the field, would have been materially affected.

3. Ex. 2 is the written statement filed on behalf of the respondent No. 1. He denied that his nomination forms did not mention his Tribe or that he did not mention the fact that his Tribe was a Scheduled Tribe in the area concerned. He then further stated as follows :—

"In this connection, I beg to point out that the Gujarati version of the nomination form supplied by the Returning Officer's office to the candidates does not contain a declaration form requiring mentioning of the tribe concerned. The part pertaining to the declaration as printed in the said form in its Gujarati version requires only the name of the candidate concerned to be declared".

Other contentions are also mentioned, but I do not reproduce them here because they are reflected in the issues at ex. 3, which are reproduced below :—

(1) Whether the petition is liable to be dismissed under the R. P. Act 1951 for not impleading all the candidates as required u/s. 82(a) of the R. P. Act, 1951 (Mr. H. M. Mehta to clarify who other possible candidates are ;

(2) Whether the petition is not verified as required by sec. 83(1) of the Act;

(3) Whether the petition is not accompanied by the proper deposit of the amount of security of costs and hence whether it is liable to be rejected ;

(4) Whether the petition is time-barred in view of S. 81 of the R.P. Act, 1951;

(5) Whether the non-mention of the particulars of the respondent No. 1's caste or tribe in the nomination paper rendered the nomination paper invalid and consequently his election bad at law ;

(6) Whether the petitioner is a member of "Rathwa" tribe, a schedule tribe, declared as such by the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950 ;

(7) Is section 33(2) of the R.P. Act ultra vires;

(8) Is the rule regarding filling-up the nomination paper and prescription of the nomination paper as given in form 2(a) of the counduct of election Rules, 1961 void as alleged ?

(9) What Orders ?

4. No arguments were advanced at any stage of the hearing of this petition regarding the issues Nos. 1, 2, 3 and 4, and even on merits, I find little force in these four contentions. I find that this petition does not require any other candidate, except the candidate whose election has been challenged, to be made a party, particularly when the petitioner has not pressed his prayer for getting himself declared duly elected. Even otherwise, the respondent No. 2, who was the only other contestant in the field, was already a party. No fault has been shown in respect of the verification of the petition. The deposit was already made and the petition was presented to this court on 19-2-80 within 45 days of the declaration of the result. So the question of bar of limitation under sec. 81 of the R.P. Act does not arise. Under the said provision, the election petition is required to be filed within 45 days from the date of the election of the returned candidate. In the case on hand, the elections were held in January 1980 and the result was declared on 6-1-80. The last date for filing, therefore, would be 20-2-80.

5. So, the only question that arise is whether the provisions of Sec. 33(2) of the R.P. Act 1951 and of Rule 4 and the Form 2-A contained in the Conduct of Election Rules 1961 are ultra vires and if they are not, whether the nominations of the respondent No. 1 can be said to have been improperly accepted.

6. The question of vires of these provisions was not at all argued by the learned Advocate General, who appeared for the respondent No. 1 along with Mr. H. M. Mehta. The Division Bench of this court in the case of Raju V. B. vs. Chief Electoral Officer AIR 1976 Guj. 66, has examined the law on the point and has concluded that sections 33(1), 34, 35, 37, 39 etc. are not ultra vires the constitution. It was emphasised in that case that the right to stand at the election is not a constituional right, but it is a satutory right and the statute that creates the right, can circumscribe it also. It was held there that the right to stand at the election to the House of People or to the Council of States is not a Constitutional right guaranteed to a person under Article 84 of the Constitution of India. The Division Bench held that Article 84 simply provided that a person should not be qualified to be chosen to fill a seat in Parliament unless he had certain qualification, but it did not give an unfettered right to a person who is a citizen of India to contest election without complying with the obligations entailed by the statute made in that behalf by Parliament. No doubt section 33(2) of the R.P. Act was not directly on the anvil of the Division Bench of this Court in the case of Raju V. (Supra), but what the Division Bench has observed in respect of sec. 33(1) and other provisions of the Act can still squarely apply to sec. 33(2) as well. I do not find that the provisions of sec. 33(2) or Rule 4 and Form 2A are in any way hit by the ultra vires character.

7. This brings me to the moot and only question that has arisen in this petition. As already said by me above, the forms presented by the respondent No. 1 were four in number and they are produced at Annexures A-1 to A-4. The first part of the form is to be filled in by the proposer. The proposer stated that a candidate named 'Rathwa Amarsinghai Virayabhai' was being proposed by him. It is, therefore, evident that Rathwa Amarsingbahi Virayabhai is the name of the candidate. The word "Rathwa" appearing first in this group of three words is a part of the name and obviously, therefore, it is surname. The second part of the name is required to be filled in by the candidate. The lower part of that second section is to be filled in by the candidate, who contest the election as a member of the Scheduled Tribe or Caste. The English version of that form in that part reads as follows :—

"I further declare that I am a member of the........ ....caste/tribe, which is a scheduled caste/tribe of the State of.................in relation to........... . (area) in that State.

(Signature of candidate)"

The Gujarati version of that part is also required to be reproduced from Annexure A-1. It reads as follows:—

[Gujarati version not printed]

In this part also, the respondent No. 1 has signed as Rathwa Amarsinghbhai Virayabhai. It is, therefore, evident that the epithet Rathwa' prefixed to the name and father's name was clearly intended to be the name of the respondent No. 1 and the atempts made in the course of the hearing of this petition that this epithet "Rathwa" appended to the name Amarsingbhai Virayabhai was not the surname, but was only the Tribe name is to be rejected as a belated attempt on the part of the respondent No. 1 make good his point. I repeat that both in the first part of form 2-A as well as in his signature part at part 2, the word "Rathwa" has been put in conjunction with the name by prefixing it and, therefore, the only reasonable interpretation that can be pleased on the word "Rathwa" is that it is prefixed to the name of the respondent No. 1 as his surname and not as an indication of the Scheduled Tribe to which he belongs. I am not oblivious of the fact that people of some caste or tribe adopt the name of their caste or tribe also as their surname. But equally it is a matter to be judicially noticed that there are surnames amongst people in India, which surnames may or may not be suggestive of the caste. So it is difficult to subscribe to the proposition that surnames are not used by these Rathwa tribe people in that area, that they never use surname and that they either prefix or suffix the word "Rathwa' to their names only for the purpose of indicating their tribe.

8. In this connection, the oral evidence led by the parties deserves to be dealt with on behalf of the petitioner. He alone has been examined at ex. 5. The respondent No. 1 has examined himself at ex. 8 and he has examined two witnesses Shri Harivallabhdas Parikh at ex. 23 and Shri Vishnubhai Purohit at ex. 25. No other oral evidence has been led.

9. The petitioner in his evidence stated as follows in paragraph 6 :—

> "People of the scheduled tribes at times annex to their names the surnames other than the names of their tribes, as per example, some people of the scheduled tribes call themselves as Barias also.

Curiously enough, the above-mentioned statement made by him in his examination-in-chief was not at all controverted, and so that evidence stands on the record as unchallenged evidence. The respondent No. 1 in his evidence at ex. 8, however, stated that :

> "To my knowledge, people of my Rathwa tribe call themselves Rathwa alone and do not adopt any other surname..........I have never come across any member of the Rathwa tribe calling himself by a surname other than Rathwa. We people of the Rathwa tribe do not have any surname as such, but we employ our tribe name as the first word of our name........"

In his cross-examination, however, he had to admit that he had no idea about the number of persons of Rathwa tribe in Naswadi taluka or Pavi-Jetpur, and that he had no idea as to whether the people of Rathwa tribe are located in any other part of the other State in India. He further stated that in about 125 villages in Chhotaudepur takula, there lived people of Rathwa tribe and that out of the people of the Rathwa tribe in Chhotaudepur takuka, he must be knowing about 50 to 60 families. This evidence of the respondent No. 1, therefore, showed that his assertion that people of the Rathwa tribe never employ any surname as such, but mention Rathwa word as indicative of their tribe, was obviously an afterthought on his part, in the sense that the petitioner was not put this case, despite his assertion otherwise.

10. The next witness examined on behalf of the respondent No. 1 is Shri Hrivallabhdas Parikh, ex. 23, dedicated social worker, as he appeared to be from his examination-in-chief. He has got service record of about 33 years with Adivasis. He, in paragarph 2 of his evidence stated as follows:—

> "There is no custom among the adivasis to have any surnames prefixed or suffixed to their names but they prefix or suffix their tribe names to their names".

This witness, however, being true to this oath almost volunteered and stated at once as follows :—

> "However, when they have to address their sons-in-law or such distinguished people, they use the surnames like Dharva or some such other surnames. They never use the term "Rathwa Kolis" though the then Maharaj of Chhotaudipur had made an attempt to call them as such in order to show that the Rathwas under his rule were superior to Rathwas in the other territory. Because of this past legacy, some Rathwas still use epithet as Rathwa Kolis or even Kolis either as a prefix or a suffix.........

This candid statement made by a man of distinguished public service goes to show that Rathwas do not invariably use the word "Rathwa" as the surname. Some Rathwa people of Chhotaudepur taluka call themselves as Rathwa Kolis and this is the surname, which they prefix or suffix to their names. Referring to the voter's list, that was brought to his notice, he admitted that "there is reference to Ra. Ko. Pataliabhai Jagalabhai". I know him personally. In fact, he was Rathwa by tribe as there is no separate tribe known as Rathwa Kolis'. This sentence from the deposition of Shri Parikh shows that Rathwas do not necessarily use the epithet Rathwa as they prefix or suffix to their names by way of invariable concomitant, Rathwas do at times have surname Kolis and the people of distinction or honour of commanding respect are having surnames like Dharva or some such other names. Despite his extensive services, stretched over a number of villages, the witness was fair enough to admit that he could not speak about all the villages in those talukas in connection with the residents thereof, but he could certainly speak in connection with some villages of those talukas. The fairness of this witness was evident when he admitted that one Jasvantbhai, following the lawyer's occupation, was known as Baria and said Jasvantbhai had contested the election as the member of the Rathwa tribe. The witness no doubt stated that the said advocate had filed an affidavit that though he was using the surname Baria, he was in fact belonging to Rathwa tribe. The witness further candidly admitted that there were some instances that had gone to his information in which people holding surnames Barias, claimed to be belonging to Rathwa tribe and they did get benefit also as such, but they for that purpose used to file affidavits to that effect. The witness further admitted that he had not conducted any systematic survey or study, but what he spoke about Rathwa tribe, was based on his contact with the people whom he happened to meet in the course of his extensive social services. This evidence of Mr. Parikh in my view explodes the defence of the respondent No. 1 that Rathwas invariably apply the epithet Rathwa to their names and that too for the purpose of indicating their tribe and not by way of their surnames. People belonging to Rathwa tribe are shown to be possessing the surname Rathwa Koli, or as it is in the case of Jasvanthbhai the surname Baria and the witness had come to learn that many other pepole with such surnames also went forth with an assertion that they belonged to Rathwa tribe. In my view, the evidence of Shri Parikh, which partially deserves a good deal of credit, also supports the say of the petitioner rather than that of the respondent no. 1

11. The last witness is Vishnubhai Purohit, ex. 25, working as the worker of Khet Mazdoor Parishad with his headquarters at Baroda. This witness claims to have knowledge about the social customs prevailing among Rathwas located in Rath area (i.e. Rathwas' area) but his claim to be a well conversant man on that subject was belied when he, unlike Shri Parikh, stated in his examination-in-chief itself that he did not know if there were any Dhor Bhils in that area. He had to admit that at some places outside those areas of his operation, there was practice to write Rathwa Kolis instead of Rathwa simple. He too had not any occasion to conduct a systematic study about the origin of Rathwa tribe. He admitted that he knew Vakil Jasvantbhai, whose surname was Baria. The witness, however, added that he did not know if said Jasvantbhai belonged to Rathwa tribe or that he had contested the election as a member of the Rathwa tribe in a reserved seat. The witness, claiming to be a social worker of many years' standing, was not ready to speak known facts like Mr. Jaswanthhai's contest at election.

12 So as far as the oral evidence on the record goes, the respondent no. 1's assertion that the epithet Rathwa either prefixed or suffixed to the name is necessarily indicative of the tribe and it is not surname, is difficult to be appreciated and accepted.

13. Inviting my pointed attention to Forms, annexures A-1 to A-4, it was urged that in the declaration part 2 of the firms, the reference to the ward "Rathwa" as preceding the name and father's name of the respondent no. 1 shown, by necessary implication, be understood to have reference to the Tribe name. I have already stated in this connection that thre is an inconsistent plea in the written statement on this point. In one breath, it was asserted that the words "Rathwa Amarsinghbhai Virayabhai" in those f.oms were indicative of the Tribe's name and it was asserted in the next breath that the Gujarati version of the nomination form supplied by the Returning Officer's office to the candidate did not contain a provision requiring mentioning of the tribe concerned. Technically speaking, a party in its pleading may take inconsistant pleas but when it comes to appreciation on merits the court is free to draw its inferences. From the above quoted statement in the pleading, it appears clear that the respondent no. 1 while filling in the forms Annexures A-1 to A-4, was under the impression that is was not required to be mentioned in the forma as to which specific tribe notified by the President in his order of 1980 he belonged. The order in question is shown as Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1980 issued by the president by virtue of powers conferred on him by clause (i) of Article 342 of the Constitution of India. The order is styled as the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950. In that order, in part IV, various tribes of Gujarat are set out as the Scheduled Tribe recognised by the President. The Tribe of Rathwa in Gujarat is recognised as such without any reference to the particular area of the State.

14. It cannot be denied that this respondent No. 1 might have been misled by the Gujarati Form, which purports to be the Gujarati Version of the original English form. The distant possibility of this nature cannot be eliminated. It also cannot be denied that the respondent No. 1 had contested the election as a candidate for the reserved seat on the earlier occasion and his form at that time also was almost similar to the forms, Annexure A-1 to A-4. If any evidence is required to be permitted and appreciated, it is inevitable to hold in this case that the respondent No. 1 had successfully proved before the Returning Officer by adducing evidence, and before me too by adducing evidence, that he in fact belongs to Rathwa Tribe. What is contended before me is that if the Forms, as presented to the Returning Officer, suffer from the non-compliance with the mandatory provisions of sec. 33(2) of the R.P. Act, the further enquiry is redundent or fruitless. This is the point, which I will be required to consider in the light of the provisions of sec. 33(2) of the R. P. Act, 1951.

15. I have already quoted above sec. 33(2) of the R.P. Act. Prima facie, it would appear that the text of this sub-section would allow no scope for any interpretation by resort to extraneous aides. It is the cardinal principle of interpretation that if the text of any provision is clear and unambiguous and is susceptible of only one reasonable meaning, the meaning as is apparent and evident has to be deduced. The other aids of interpretation are required to be sought for if the text of the said provision is susceptible of two or more interpretations or the text, as it is, does not afford a clear expression of the legislative intent. The legislature has put the mandate in very emphatic terms. It states that the candidate shall not be deemed to be qualified to be chosen to fill that seat, unless his nomination paper contains a declaration by him specifying the particular caste or tribe of which he is a member and the area in relation to which that caste or tribe is a schedule caste or, as the case may be, a scheduled tribe of the State. I am not obligious of this circumstance that or of the auxiliary very "shall" is not necessarily indicative of the mandatory character of the provision, but the text enjoins on the Returning Officer that the nomination papers shall not be accepted and the candidate shall not be deemed to be qualified to be chosen to fill that seat, unless his nomination paper contains a declaration by his specifying the particular caste or tribe of which he is a member. The text of this sub-section, in my opinion, is not susceptible of any other even remotely possible meaning.

16. The Supreme Court had an occasion to examine the character of the text of Sec. 33(2) of this Act in the case of V. V. Giri vs. D. Suri Dora & Others, AIR 1959 S.C. 1318. The Supreme Court in this connection, speaking through the majority Judgment, has laid down as follows :—

> "A member of the schedule tribe is entitled to contest for the reserved seat and for that purpose he can and must make the prescribed declaration (emphasis supplied by me)."

In paragraph 12 of the said reported judgment, the following observations have been made by the majority, speaking through Gajendragadkar J., as he then was:—

> "The effect of S. 33(2) is that unless a member of the scheduled tribe makes the required declaration, he would not be entitled to claim election to the reserved seat..."

It is no doubt true that the scope of Sec. 33(2) came to be examined by the Supreme Court in the said V. V. Giri's case (supra), in the context of sec. 54(4) of the Act. In those days, there were double member or multi-member constituencies and the provisions of the Representation of People Act, 1950 had come to be considerably amended in the year 1966 by Act No. 47 of 1966. As per the amendment of 1966, the double member or multi-member constituency came to be given a permanent go-bye on and from that date, all constituencies came to be made single member constituencies. However, what the Supreme Court observed with respect to the meaning of the provisions of sec. 33(2) does not get its worth in any way detracted from. So, in my view, it is not possible to hold that the mandate of Sec. 33(2), if at all applicable, it in any way directory and not fully mandatory.

17. On behalf of the respondent No. 1, a few authorities were pressed into service. The first is the case of K. Parthasarathy vs. C. Nataraiadavar & Ors., AIR 1959 Madras-156. In that case, sec. 33(2) was examined in the light of sec. 36(4) and it was held that the nomination paper filed by a candidate for the reserved seat of a scheduled caste was valid, even though the provisions of sec. 33(2) of the Act were not complied with in so far as the candidate there stated that he was a Hindu Harijan, but he did not specify to what particular scheduled caste he belonged. It was held in that case that the defect of sec. 33(2) "was not of such substantial character as to justify the rejection of the nomination paper."

18. Another case cited on behalf of the respondent no. 1 is the case of Karnail Singh vs. Election Tribunal Hissar & Ors. 10 Election Law Reporter 189. There also, it was held that ommission to state part of electoral roll in which candidate's name appears was not vital and incidentally sec. 33(2) was examined in the light of sec. 36(4) of the Act. In that case, it was held as follows :—

> "The only defect pointed out was that the name of the sub division was not stated therein, but on the evidence it was quite clear that there was no difficulty in identifying the candidate and the candidate himself pointed out to the Returning Officer the entry of his name in the electoral roll."

It appears that sec. 33(2), though mentioned in the Head-note, does not find place in the body of the judgement at page 190. It appears from the facts of the case that reference to sec. 33(2), even if it be there in the part of the judgement not reported, must obviously be obiter.

19. The third case is the case of Harnam Singh vs. Tirath Singh I.L.R. 1964 Vol 1 Punjab 798. One of the two questions before the appellate Bench of the High Court in that election appeal was whether the rejection of the nomination paper in question was valid. In that case, the candidate, though a member of the Scheduled Tribe, was not contesting a reserved seat with the result that sec. 33(2) would clearly be inapplicable to his case. The observations that are, therefore, made there are obiter. Moreover, as we can find at page 812 "no decided case nor any sound principle has been cited at the bar in support of the appellant's contention, which must be repelled". So, this case is of little consonce.

20. As far as sec. 33(2) of the R.P. Act is concerned, the Supreme Courts judgement in V.V. Giris case (Supra) makes the position clear. I have already referred to the said judgement. The Madras High Courts judgement, the facts of which are clearly analogous to the facts of the case on hand, cannot be said to be expounding good law in the face of V.V. Giri's case (Supra). Even on my own and interpreting Sec. 33(2) of the Act, I would hold that the text of Sec. 33(2) does not admit to any other interpretation, except the mandatory character thereof.

21 The moot question and an important question that was, however raised on behalf of the respondent no 1 by Mr Advocate General opposing with Mr H M Mehta was, that section 33(2) of the R P Act, 1951 has lost its significance, though it continues to be there on the statute book. Mr Advocate General in this connection took me through the provisions of the representation of People Act, 1950, as it was prior to its amendment in the year 1966 by Act no 47/66 He invited my pointed attention to the following sections, which are reproduced below —

3(1) The allocation of seats in the house of the people shall be as shown in the first Schedule,

(2) To each State specified in the first column of the First Schedule there shall be allotted the number of seats specified in the second column thereof opposite to that State

Note —This section and Sec 1 prescribes the total number of seats in the House of People allotted to each State

4(1) The seats allotted under section 3 to the State of Jammu and Kashmir and to the Andaman and Nicobar I lands shall be seats to be filled by persons nominated by the President,

(2) Save as aforesaid, all the other seats in the House of the people allotted to the States under that section shall be seats to be filled by persons chosen by direct election

5 For the purpose of elections to the House of the people, there shall be the constituencies as provided by sec 6 or by order made thereunder, and no other constituencies

6(1) Each State to which only one seat is allotted in the First Schedule shall form one constituency

(2) As soon as may be after the commencement of this Act, the president shall, by order, determine—

"(a) The constituencies into which each State to which more than one seat is allotted in the First Schedule shall be divided

(b) the extent of each constituency,

(c) the number of seats allotted to each constituency, and

(d) the number of seats, if any reserved for the scheduled castes or for the scheduled tribes in each constituency,'

It is not disputed that ever since the amendment in that Act, the double member and multi-member constituencies have become a matter of the past Sec 33(2) was there in this very form in those days and Mr Advocate General with emphasis urged that the text of sec 33(2) was such as would be applicable only to the situation where in a constituency, there were two or more seats, one or more of which was or were reserved for a member of the Scheduled Caste or a Scheduled Tribe He in this connection stressed the word "any" occurring there It must be fairly conceded that the word "any" denotes "anyone" and when there is reference to one, ordinarily there would be reference to two or more seats also, when sec 33(2) was there prior to the constitution of the single member constituencies it was required to be interpreted to mean that where in a parliamentary constituency any seats one out of more is reserved for a candidate of the Scheduled caste or tribe the member would be required to specify the specific caste or tribe so that out of a number of candidates in that constituency it could be ascertained at a sheer glance as to who are the candidates for a reserved seat and who are the candidate for a general seat The argument in so far as it goes to this stage appears to be sound The further argument of Mr Advocate General, however was that the provisions of sec 33(2) lost all significance and importance the moment there came to be provided the single member constituencies He therefore urged that sec 33(2) should be treated as otiose by me He for that purpose, sought reliance on some observations of the Supreme Courts judgement in V V Giri's case (Supra), already referred to by me In that case, the illustration appended to Sec. 54(4) of the R P. Act, 1951 was treated by the Supreme Court as otiose in some respects Said sec 54(4) had an illustration which is reproduced below (it is to be noted that this whole sec 54 has been deleted from the statute by Representation of People Amendment Act, 1961, being Act no 40/61) —

'Illustration —At an election in a constituency to fill four seats of which two are reserved there are six candidates A B,C,D,E and F, and they secure votes in descending order, A securing the largest number, B, C and D are qualified to be chosen to fill the reserved seats, while A E and F are not so qualified The Returning Officer will first declare B and C duly elected to fill the two reserved seats, and then declare A and D (not A&E) to fill the remaining two seats"

In paragraph 15 of the said reported judgment (V V Giri's case Supra), the Supreme Cou t has observed as follows:

"Whilst we are dealing with S 54 we may incidentally refer to the appellant's argument based on S 8(2) (a) of the Delimitation Act, which provides that in every two-number constituency one seat shall be reserved either for the scheduled castes or for the scheduled tribes and the other seat shall not be so reserved It is urged that in view of this provision, the case contemplated by the illustration to S 54(4) is not likely to occur any more and in that sense the illustration has become 'Otiose' That may be true But even so the significance of the illustration lies in the fact that it clarifies and explains concretely how the reservation of seats for the depressed castes and tribes will actually work out in elections in the relevant constituencies"

In one sense, the Supreme Court agreed that the importance of sec 54(4) and the illustration appended to it was no more but the Supreme Court did not say that the provisions came to be effected for all purposes It has emphasised That the significance of the illustration lay in the fact that it clarified and explained concretely how the reservation of seats for the depressed caste and tribes will actually work out in elections in the relevant constituencies The fact that sec 54(4) came to be deleted as a consequence of the amending Act, no 40/61 by Sec 12 thereof will effect from 20-9 61 shows that the Parliament is alive to the redundency of any provisions Despite the change in the constitution of constituencies the Legislature thought it wise to retain sec 33(2) on the Statute book Mr Advocate General wanted me to hold that Parliament through over sight forgot to delete this provision, when the amending Act of 1966 came to be enacted It is not ordinarily safe to attribute this sort of slip to an August body like Parliament Apart from this general proposition there is a clear indication in sec 33 itself about the Legislature's consciousness about the implications of the amendments of the year 1966 A big proviso came to be added to sub sec (4) of sec 33 by the very Amending Act of 47/66 by sec 29 thereof It is, therefore, reasonable to because that despite the change in the constitution of the constituencies by making them single member constituencies the Legislature wanted to retain sub-sec (2) of sec 33 of the R P. Act, If the purpose of sec. 33(2) was the only purpose to distinguish the candidates for reserved seats from those for general seats, the argument advanced by Mr Advocate General perhaps would have held the field The purpose of Sec 33(2), however, is not that only purpose to be served Over and above the purpose already specified by Mr Advocate General, the purpose appears to give a choice to the candidate of the scheduled caste or tribe to opt for the additional benefit of contesting on the reserved seat To me it appears that the major purpose of the Parliament in enacting sec 33(2) in the mandatory form is that out of a number of castes and tribes, which would be obviously notified by the president the candidate must mention in his nomination form which one, out of a number of castes or tribes he is belonging to The election forms are open to inspection at the hands of a rival candidate Such a rival candidate or his agent is empowered to object to the nomination paper of the other candidate In order to effectively object to the claim of candidate to be belonging to one or the other of a number of seats or tribes he is to be given a legitimate notice or information so that he may ascertain whether the claim is

well-rooted or not. A parliamentary constituency is ordinarily a very big one. Comparatively smaller, but nevertheless quite extensive would obviously be the constituency for a state Legislative Assembly or council. In some cases, rival candidate, who aspires for a reserved seat. In order to give notice to the other intending objectionist, the Parliament provided that out of a number of castes or tribes, the claimant of this additional benefit of candidature for a reserved seat must specify to what caste or tribe he belongs. The objectionist cannot be and is not intended to be allowed to remain in a nebulous state of mind. It is with this evident purpose in mind, which must be existing even prior to 1966 sec. 33(2) is retained by the parliament, despite being fully alive to the constitution of single member constituencies.

22. Mr. Advocate General in this connection had emphasised the words "any seat" along with the words "that seat" occurring in the latter part of that sub-section and urged that the phrase "that seat" was obviously referable to the earlier words "any seat". When the Parliament, despite the constitution of single member constituently, retained sub-sec. (2) of Sec. 33, it is more advisable to read the section by reading 'a' for 'any' rather than ignoring the entire statutory provision. Ordinary presumption of law is that the legislature does not speak anything, which is devoid of any meaning. The retention of sec. 33(2), even after 1966, therefore, is to be understood to be indicative of the parliament's desire to continue to achieve the earlier purpose of posting the would be objectionist with the readily available material for his further search and scrutiny, so that within a matter of a few days available to him between the date of filling of the nomination papers and the date of scrutiny, he collects the requisite material and places it and prosses his point.

23. As an extension of his argument, Mr. Advocate General urged that Article 14 of the Constitution of India would be attracted, if one person fills in the form by writing Rathwa in the form and another person does not write so. but the form is sufficiently indicative of the man being of that tribe It is difficult to appreciate this argument. This argument proceeds on the assumption that both the forms are validly accepted. The argument further proceeds on the assumption that further evidence could be led before the Returning Officer in order to make good the deficit, if any, When sec. 33(2) cuts at the nomination forms itself, the scope for any invidious different treatment would hardly arise.

24. Mr. Advocate General further argument in this connection was that even though change in the constitution of constituencies was effected in the year 1958, the original form like Form 2-A continued to be operative and, therefore, the difficulty of the nature, that has arisen in this case, would arise. The argument was put forward in support of the plea that sec. 33(2) and other allied provisions of Rule 4 and Form 2—had become nugatory in importance, but when I do not uphold the main argument, the subsidiary argument pressed by Mr. Advocate General cannot be accepted.

26. Lastly, it was urged that the Gujarati form, as was supplied by the office of the Returning Officer, had misled the respondent, who for no fault of his, comes to suffer. In a society where rule of law prevails, a man is presumed to know the law, including sec. 33(2) of the Act. A person, who puts forth himself as a candidate for Parliament, is expected to know the law of the land and this alleged mistake cannot be allowed to have its sway in the hands of a careful candidate, there is no possibility of Gujarati form causing misleading.

26. It was then urged that a technical mistake like the one on hand should not be allowed to set at naught the cumbersome and costly procedure of election and relience in this connection was placed on sec. 36(4) of the R. P. Act. It was urged with considerable and appreciable venemance that the provisions of sec 36(4) had an over-powering effect over the provisions of sec. 33(2) and the defect in this case should be held to be "not of a substantial character". Sec. 36(2) deals with the scrutiny of nominations. Sub-sec. (4) of sec. 36 makes a general provision that if the defect is not of a substantial character. it should not be allowed to sway the judgment of the Returning Officer. The question again would turn to the character of the requirement under sec. 33(2) of the R. P. Act. When the Parliament in very emphatic language ordained that the nomination papers shall not be accepted, it is to be presumed legitimately that the Parliament treated the requirement of sec. 33(2) as of substantial character.

27. In above view of the matter the election petition is required to be allowed and the election of the respondent no. 1 is set aside, because there was improper acceptance of his nomination paper and the result of the respondent no. 1 has been materially affected thereby, the election of the respondent no. 1 is hereby set aside. The respondent no. 1 to pay costs of the petitioner, which are assessed at Rs. 500. The High Court to intimate the substance of this decision to the Election Commission and then Speaker of the House of Parliament as soon as possible and as soon as may be thereafter to send to the Election Commission an authenticated copy of this decision.

28. At this stage, Mr. H. M. Mehta, the learned advocate appearing for the respondent no. 1 applied for stay of the operation of this order under sec. 116-B of the Representation of the People Act, 1951. The operation of this order is stayed for a period of three weeks, after the receipt of the certified copy of this judgment, which shall be applied for and obtained urgently by the respondent no. 1.

[No. 82/GI/(2/1980)/81]

DHARAM VIR, Under Secy.
Election Commission of India.

आदेश

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1981

आ० अ० 280.—यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नवम्बर, 1978 में हुए लोक सभा के लिए उप निर्वाचन के लिए 20—चिकमंगलूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री खान हैदर अली खान, प्रोप्राईटर टिप्पू ट्रैवल्ज, नम्बर 24/7, जे० सी० रोड, बैंगलोर-560002, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं;

और यतः, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री खान हैदर अली खान को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

[सं० कर्नाटक-लो० स०/20/78 (उप) (4)]

ORDERS

New Delhi, the 15th April, 1981

O.N. 280.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri Khan Hyder Ali Khan Proprietor, Tippu Trovels, No. 24/7, J. C. Road, Bangalore-560002, a contesting candidate for Bye election to the House of People held in November, 1978 from 20-Chikmagalur Parliamentary Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure;

Now, therefore, in pursuance of section 10-A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri Khan Hyder Ali Khan to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. KT-HP/20/78(bye)/(4)]

आ. अ. 281.—यत:, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मई 1980 में हुए तमिलनाडु विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन के लिए 194-तिरुपाथूर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री ए. विराभाथिरन, 6/13-40 सन्नथी स्ट्रीट तीरुप्पाथूर, रामानाथा पुरम जिला (तमिल नाडु) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित समय के अन्दर तथा रीति से अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं ;

और यत:, उक्त उम्मीदवार ने, सम्यक सूचना दिए जाने पर भी, इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है और निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उसके पास इस असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा उक्त श्री ए. विराभाथिरन को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है ।

[सं. त. ना.—वि.-स./194/80 (89)]

आदेश से,

अ. कु. चटर्जी,

अवर सचिव, भारत निर्वाचन आयोग

O.N. 281.—Whereas the Election Commission is satisfied that Shri A. Virabathiran, 6/13—40 Sannathi Street, Tirupattur, Ramanathpuram District (Tamil Nadu), a contesting candidate for general election to the Tamil Nadu Legislative Assembly held in May, 1980 from 194-Tirupattur Constituency, has failed to lodge an account of his election expenses within the time and in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the Rules made thereunder;

And whereas the said candidate, even after due notices, has not given any reason or explanation for the failure and the Election Commission is satisfied that he has no good reason or justification for the failure ;

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the said Shri A. Virabathiran to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a period of three years from the date of this order.

[No. TN-LA/194/80(89)]

By Order,

A. K. CHATTERJEE, Under Secy.
to the Election Commission of India

100 GI/81 -5

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981